आदिवासी और लोककला के संरक्षण और विकास संबंधी सलाहकार समिति

2923. **श्री कुम्भा राम आर्य** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आदिवासी और लोककला के संरक्षण और विकास संबंधी सलाह कार समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ख) इस समिति की पहली बैठक में की गई सिफारिशों पर की गई और की जान वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समिति की पिछली बैठक कब हुई थी और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) सलाहकार समिति की संरचना इस प्रकार थी:—

1. शिक्षा मंत्री	अध्यक्ष
2. अध्यक्ष, संगीत नाटक अकादमी	सदस्य
3. अध्यक्ष, ललित कला अकादमी	—वही—
4. रजिस्ट्रार जनगणना आयोग	—वही—
5. संयुक्त सचिव, जन-जातीय कल्याण, गृह मंत्रालय	—वही—
6. अध्यक्ष, साहित्य अकादमी	—वही—
7. अध्यक्ष, आदिवासी सेवा संघ	—वही—
8. अध्यक्ष, हाथकरघा बोर्ड	—वही—
9. अध्यक्ष खादी तथा ग्राम-उद्योग बोर्ड	—वही—
10. सचिव, श्रम विभाग, भारत सरकार	—वही—
11. अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	—वही—
12. निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्	—वही—
13. निदेशक भारतीय मानव-विज्ञान सर्वेक्षण, कलकत्ता	—वही—
14. निदेशक (योजना), समाज कल्याण विभाग, भारत सरकार	—वही—
15. श्री सुशील भट्टाचार्य, लेखक	—वही—
16. प्रोफेसर संखो चौधरी, कलाकार	—वही—
17. श्रीमती दुर्गा भागवत, लेखिका तथा मानव-विज्ञानी	—वही—
18 श्री एच० शाह, निदेशक, जन जातीय संग्रहालय, अहमदाबाद	—वही—
19 डा० बी० डी० शर्मा, जन-जातीय आयुक्त, भोपाल	—वही—
20. संयुक्त शिक्षा सलाहकार (संस्कृति)	सदस्य सचिव

(ख) और (ग) 21-11-1978 को इस समिति की केवल एक बैठक हुई थी और इसकी सिफारिशों पर नई दिल्ली में दिनांक 2 जुलाई, 1979 को हुई एक बैठक में राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों में कला और संस्कृति के प्रभारी मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया गया था । सम्मेलन ने सिफारिश की कि जन-जातीय कल्याण संगठनों और राज्य सरकारों के जन-जातीय विकास विभागों और उद्योगों को भारत में जन-जातीय समाज के सांस्कृतिक पहलुओं की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए, स्कूल तथा

कालेज पाठ्यचर्या में ऐसे पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए जाने चाहिए, जो छात्रों को ग्रामीण तथा जन-जातीय स्तर की समृद्ध तथा विविध सांस्कृतिक परम्पराओं की जानकारी प्रदान कर सके और उन्हें इन परम्पराओं में शामिल होने के योग्य बना सके। सम्मेलन ने यह भी सिफारिश की कि जन-जातीय भाषाओं और बोलियों के विकास के लिए राज्य स्तर पर विशेष संगठन स्थापित किए जाने चाहिए।

Central Assistance for Lasariya Nullah

2924. SHRI KUMBHA RAM ARYA: Will the Minister of IRRIGATION be pleased to state:

(a) the financial assistance given by the Central Government for Lasariya nullah, constructed by the Government of Punjab to drain out rain and logged waters;

(b) the total expenditure incurred on the construction of Lasariya nullah; and

(c) the reasons why Rajasthan was not supplied water from this nullah for irrigation purpose even after the Central Government's decision in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF IRRIGATION (SHRI Z. R. ANSARI): (a) and (b). The Punjab Government has reported that no financial assistance was given by the Central Government for the Lasariya Nullah. The expenditure incurred by the Punjab and the Haryana Governments is Rs. 207.16 Lacs.

(c) In case the Hon'ble Member can give some further particulars regarding the decision of the Government of India referred to in the Question, necessary information will be collected and furnished.

राजस्थान के सीकर जिले में शाखा डाकघर तथा सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

2925. श्री कुंभा राम आर्य : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के सीकर जिले में चालू वर्ष के दौरान कुल कितने शाखा डाकघर और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोले गए; और

(ख) वर्ष 1980 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव): (क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सीकर जिले में सात शाखा डाकघर तथा एक सार्वजनिक टेलीफोन घर खोला जा चुका है।

(ख) 1980-81 में सीकर जिले में 7 शाखा डाकघर तथा सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने का लक्ष्य रखा गया है। सार्वजनकि मांग तथा भंडार उपलब्ध होने पर सार्वजनिक टेलीफोन घर खोले जायेंगे।

चावल मिल संघ द्वारा मांग-पत्र

2926. श्री राम लाल राही : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल मिल संघ ने सरकार को एक मांग-पत्र पेश किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) : चावल मिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी अखिल